



सामान्य रपिर्गटि मानक: OECD

प्रलिमिन्स के लिये:

सामान्य रपिर्गटि मानक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD), [सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान](#) (Automatic Exchange of Information- AEIO), G20, [कर चोरी](#), [आधार कषण एवं लाभ हस्तांतरण](#) (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS)।

मेन्स के लिये:

सामान्य रपिर्गटि मानक के बढ़ते दायरे की आवश्यकता।

चर्चा में क्यों?

भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) देशों के बीच सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information- AEIO) के तहत अचल संपत्तियों जैसे गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को शामिल करने के लिये [G20](#) समूह में सामान्य रपिर्गटि मानक (Common Reporting Standard- CRS) के दायरे को बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

- भारत में वर्तमान में स्वचालित रूप से सूचना भेजने के लिये 78 अधिकार क्षेत्र और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने हेतु AEIO के साथ 108 अधिकार क्षेत्र हैं।
- AEOI अनवासी बैंक खातों की जानकारी को खाताधारक के गृह देश में कर अधिकारियों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है यह कर चोरी की संभावना को कम करता है।

सामान्य रपिर्गटि मानक:

परिचय:

- G20 देशों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए CRS को वकिसति किया गया था और 15 जुलाई, 2014 को OECD परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था।
- यह क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने और वार्षिक आधार पर अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ स्वचालित रूप से उस जानकारी का आदान-प्रदान का प्रावधान करता है।
- इसमें वित्तीय खाते की जानकारी साझा करना, रपिर्गटि किये जाने योग्य वित्तीय संस्थान, कवर किये गए खातों और करदाताओं के प्रकार, साथ ही वित्तीय संस्थानों के लिये एहतियाती मानक तरीके, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है।

वर्तमान रूपरेखा:

- वर्तमान में OECD की स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (AEOI) रूपरेखा कर चोरी संबंधी जाँच के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच वित्तीय खाता वविरण साझा करने में सहायता प्रदान करती है।
- कर संबंधी सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगस्त 2022 में OECD ने **करपिटो-एसेट रपिर्गटि फ्रेमवर्क (CARF)** को भी मंजूरी दी जो **करपिटो-एसेट्स में लेन-देन** संबंधी जानकारी की रपिर्गटि को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करता है।

AEIO के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता:

- AEOI के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि सूचना का उपयोग न केवल कर चोरी की जाँच के लिये किया जा सके, बल्कि **अन्ध-कर कानून लागू करने** के उद्देश्यों हेतु भी किया जा सके।
- जोखिम न केवल वित्तीय संपत्तियों पर है, बल्कि गैर-वित्तीय संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट तथा अन्य संपत्तियों को लेकर भी कर चोरी का जोखिम है, इसलिये वित्तीय से अन्य गैर-वित्तीय खातों में CRS का वसितार किया जाना आवश्यक है।

- OECD की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान भू-राजनीतिक और ऋण संकट के बीच, विशेष रूप से उन एशियाई देशों द्वारा की गई कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह की जाँच किये जाने की आवश्यकता है, जिन्हें वर्ष 2016 में राजस्व में 25 बिलियन यूरो का नुकसान होने का अनुमान है।
- एक अध्ययन अनुसार, OECD की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि एशिया की 1.2 ट्रिलियन यूरो की वित्तीय संपत्ति का 4% ऑफशोर आयोजित किया गया था, जिससे वर्ष 2016 में इस क्षेत्र को 25 बिलियन यूरो का संभावित वार्षिक राजस्व का नुकसान हुआ।

कर चोरी को प्रबंधित करने के प्रयास:

■ वैश्विक प्रयास:

- [आधार कषरण एवं लाभ हस्तांतरण \(BEPS\)](#)
- [OECD का समावेशी ढाँचा वक्तव्य](#)
- [दोहरा कराधान अपवंचन समझौता \(DTAA\)](#)

■ भारतीय प्रयास:

- [भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018](#)
- [काला धन \(अधोषति वित्तीय आय और संपत्ति\) कर अधिनियम, 2015](#)
- [धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002](#)

आगे की राह

- वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के आदान-प्रदान का विस्तार, कर संग्रह एवं गैर-कर कानून प्रवर्तन प्रयासों के लिये महत्वपूर्ण हो सकता है।
- इन पहलों को प्राथमिकता देने की G20 की प्रतिबद्धता से वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है, जिससे अंततः सभी को लाभ होगा।
- सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाने और किसी भी संभावित गोपनीयता चिंताओं को दूर करने के साथ-साथ उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये सीमाओं के पार सहयोगपूर्ण कार्य जारी रखना आवश्यक है। ऐसा करके हम एक निष्पक्ष तथा अधिक स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों को लाभान्वित करेगी।

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय चकित्सा उपकरण नीति, 2023

प्रलिमिंस के लिये:

[भारत का चकित्सा उपकरण क्षेत्र](#), [राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2021](#), [प्रधानमंत्री गतिशक्ति](#), [PPP](#), [PLI](#)

मेन्स के लिये:

राष्ट्रीय चकित्सा उपकरण नीति 2023, भारत के चकित्सा उपकरण क्षेत्र का परिदृश्य।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय चकित्सा उपकरण (NMD) नीति, 2023** को मंजूरी दी है।

- यह नीति चकित्सा उपकरण क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये एक रोडमैप निर्धारित करती है ताकि निम्नलिखित मशिनों, एक्सेस एवं सार्वभौमिकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, रोगी केंद्रित तथा गुणवत्तापूर्ण देखभाल, निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य, सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार एवं कुशल जनशक्ति को प्राप्त किया जा सके।

Policy for the Medical Devices Sector



- Cabinet approves the Policy for the Medical Devices Sector.
- Six Strategies planned to tap the potential of the Sector, with the Implementation Action Plan.
- Medical Devices Sector is expected to grow from present \$11 Bn to \$50 Bn in next five years.
- The policy is expected to meet the public health objectives of access, affordability, quality and innovation.

//

NMD नीति, 2023 की प्रमुख विशेषताएँ:

- नियामक संचालन:** रोगी सुरक्षा और उत्पाद नवाचार को संतुलित करते हुए अनुसंधान तथा व्यवसाय को आसान बनाने के लिये चकित्सा उपकरणों के लाइसेंस हेतु "सगिल वड्डो क्लीयरेंस सिस्टम" बनाया जाएगा।
 - इस प्रणाली में सभी प्रासंगिक विभाग और संगठन शामिल होंगे, जैसे- MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा DAHD (पशुपालन और डेयरी विभाग)।
- अवसंरचना को सक्षम बनाना:** आर्थिक क्षेत्रों के पास विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े चकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किये जाएंगे।
 - यह कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम और प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2021 के तहत प्रधानमंत्री गति शक्ति के दायरे में तथा चकित्सा उपकरण उद्योग के साथ अभिसरण एवं एकीकरण में सुधार के लिये राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से किया जाएगा।
- अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष को सुगम बनाना:** नीति का उद्देश्य भारत में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है, जो फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति का पूरक है।
 - इसका उद्देश्य अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों, नवोन्मेष केंद्रों, 'प्लग एंड प्ले' बुनियादी ढाँचे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना तथा स्टार्ट-अप को समर्थन देना है।
- नविश बढ़ाना:** यह नीति मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, हील-इन-इंडिया और स्टार्ट-अप मशिन जैसी मौजूदा योजनाओं के पूरक के लिये नज्दी नविश एवं सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करती है।
 - मानव संसाधन विकास:** नीति का उद्देश्य कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रम प्रदान करके चकित्सा उपकरण क्षेत्र में एक कुशल कार्यबल सुनिश्चित करना है।
 - यह भविष्य की प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण और अनुसंधान के लिये कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु मौजूदा संस्थानों में चकित्सा उपकरणों के लिये समर्पित बहु-वर्षीय पाठ्यक्रमों का भी समर्थन करेगा।
- ब्रांड पोझिशनिंग और जागरूकता निर्माण:** नीति विभाग के तहत क्षेत्र के लिये एक समर्पित नरियात संवर्द्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है जो विभिन्न बाजार पहुँच से जुड़े मुद्दों से निपटने में सक्षम होगी।

नीति का महत्त्व:

- इस नीति से चकित्सा उपकरण उद्योग को एक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, सशक्त और अभिनव उद्योग के रूप में मज़बूत करने के लिये आवश्यक समर्थन एवं दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने की उम्मीद है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।
- इसका उद्देश्य चकित्सा उपकरण क्षेत्र को रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास के त्वरित पथ पर लाना है।

- इसका लक्ष्य रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ त्वरित विकास पथ और अगले 25 वर्षों में बढ़ते वैश्विक बाज़ार में 10-12 प्रतिशत की हसिसेदारी हासिल करके चिकित्सा उपकरणों के निर्माण एवं नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरना है।
 - नई नीतियों के साथ केंद्र का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में भारत की आयात निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और शीर्ष पाँच वैश्विक निर्माण केंद्रों में से एक बनना है।
- इस नीति से वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का परिदृश्य:

परिचय:

- भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक उभरता क्षेत्र है और स्वास्थ्य सेवा उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो तेज़ी से बढ़ रहा है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान यह क्षेत्र काफी तीव्र गति से विकसित हुआ जब भारत ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा उपकरणों और वेंटिलेटर, RT-PCR कटि तथा PPE कटि जैसे नैदानिक कटि का वृहत स्तर पर उत्पादन किया था।
- यह एक बहु-उत्पाद क्षेत्र है, इसका व्यापक वर्गीकरण इस प्रकार है:

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- प्रत्यारोपण
- उपभोग्य और डिसपोजेबल
- इन वटिरो डायग्नोस्टिक्स (IVD) अभिकर्मक
- सर्जिकल उपकरण

- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन** (Central Drugs Standard Control Organisation- CDSCO) द्वारा चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 तैयार किये जाने तक यानी वर्ष 2017 तक यह क्षेत्र काफी हद तक अनियमित रहा।

स्थिति:

- जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशियाई चिकित्सा उपकरणों का चौथा सबसे बड़ा बाज़ार है तथा वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाज़ारों में से है।
- चिकित्सा उपकरण श्रेणी में वैश्विक स्तर पर भारत की वर्तमान बाज़ार हसिसेदारी वर्ष 2020 में 1.5% के रूप में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी 90,000 करोड़ रुपए) है।
- संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बाज़ार हसिसेदारी 40%, जो कि सबसे अधिक है, इसके बाद यूरोप और जापान की हसिसेदारी क्रमशः 25% और 15% है।

सरकारी पहलें:

- चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिये **उत्पादन संबंध प्रोत्साहन** (Production Linked Incentive- PLI) योजना कार्यान्वित है। NMDP 2023 मौजूदा PLI योजनाओं के अतिरिक्त है।
 - भारत सरकार ने पहले ही चिकित्सा उपकरणों के लिये PLI योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और चार चिकित्सा उपकरण पार्कों, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक की स्थापना में योगदान दिया है।
 - चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
 - जून 2021 में **भारतीय गुणवत्ता परिषद** (Quality Council of India- QCI) और चिकित्सा उपकरणों के भारतीय निर्माताओं के संघ (AiMed) ने चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता का सत्यापन करने के लिये **चिकित्सा उपकरणों के भारतीय प्रमाणन** (Indian Certification of Medical Devices- ICMED) हेतु **13485 प्लस योजना** शुरू की है।

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ:

असंगत विनियम:

- **जटिल विनियामक वातावरण** चिकित्सा उपकरण उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है।
- निर्माताओं को असंगत नियमों का पालन करना पड़ता है जो अलग-अलग मानकों और शब्दों का उपयोग करते हैं, जिससे आवश्यकताओं को समझना एवं उनका पालन करना मुश्किल हो जाता है।

अनुसंधान और विकास संबंधी चुनौतियाँ:

- भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता**, **क्लाउड कंप्यूटिंग** और **रोबोटिक्स** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग

अभी भी सीमिति है।

- इन तकनीकों को अपनाने से कंपनियों को अनुसंधान और विकास, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।

■ आयात नरिभरता:

- भारत चकित्सा उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक नरिभर है, जिससे उच्च आयात लागत और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है। आयात नरिभरता को कम करने के लिये भारत को चकित्सा उपकरणों के घरेलू वनिर्माण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

■ पूंजी तक सीमिति पहुँच:

- भारत में चकित्सा उपकरण स्टार्ट-अप्स हेतु वित्त की उपलब्धता गंभीर चुनौती है क्योंकि निवेशक प्रायः दीर्घकालिक और नियामक अनिश्चितताओं वाले क्षेत्र में निवेश करने से हचिकचाकते हैं।

आगे की राह

- भारत में नीतिनिर्माताओं को चकित्सा उपकरणों/प्रौद्योगिकी आयात पर देश की नरिभरता को कम करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है।
- भारत को अपनी चकित्सा उपकरण कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों हेतु वनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिये, स्वदेशी वनिर्माण के साथ संयोजन में भारत-आधारित नवाचार करना चाहिये, मेक इन इंडिया एवं इनोवेट इन इंडिया योजनाओं में सहयोग करना चाहिये, साथ ही छोटे घरेलू बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिये नमिन से मध्यम प्रौद्योगिकी उत्पादों का उत्पादन करना चाहिये।

स्रोत: पी.आई.बी.

कमांड साइबर ऑपरेशंस और सपोर्ट वग्स

प्रलिमिंस के लिये:

कमांड साइबर ऑपरेशंस और सपोर्ट वग्स (CCOSW), टेक्निकल एंट्री स्कीम मॉडल, साइबर सुरक्षा

मेन्स के लिये:

भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा में CCOSWs का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेना कमांडरों के सम्मेलन (Army Commanders' Conference- ACC) में भारतीय सेना ने अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने, नेटवर्क की रक्षा करने और साइबर स्पेस के प्रमुख डोमेन में खतरों का मुकाबला करने के लिये कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट वग्स (Command Cyber Operations and Support Wings- CCOSW) को संचालित करने का न्णय लिया।

सेना कमांडरों का सम्मेलन (ACC):

- ACC एक द्विवार्षिक संस्थागत कार्यक्रम है जो भारतीय सेना के लिये महत्त्वपूर्ण नीतियों पर उच्च स्तरीय वैचारिक चर्चा और न्णय लेने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- हाल ही में हुए सम्मेलन में वभिन्नि एजेंडा बडिओं, सेना मुख्यालय द्वारा प्राप्त अद्यतन सूचनाओं, परिवर्तन पहलों की प्रगति और बजट प्रबंधन पर चर्चा की गई।

कमांड साइबर ऑपरेशंस और सपोर्ट वग्स:

■ परिचय:

- CCOSWs भारतीय सेना की एक विशेष इकाई है जो अनविर्य साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करेगी।

- यह इकाई नेटवर्क सुरक्षा और भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
- यह भारतीय सेना में आधुनिक संचार प्रणालियों और नेटवर्क के बेहतर उपयोग की सुविधा भी प्रदान करेगी।
- महत्त्व:
 - नेटवर्क केंद्रिता की ओर पलायन और आधुनिक संचार प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए CCOSW काफी महत्वपूर्ण है।
 - CCOSW भारतीय सेना को ग्रे ज़ोन और साइबर युद्ध में अपने वरिधियों से एक कदम आगे रहने एवं मुकाबला करने में मदद करेगा।
 - भारतीय सेना संबंधी गोपनीयता, अखंडता और महत्वपूर्ण जानकारी की उपलब्धता को बनाए रखने में CCOSW की भूमिका महत्वपूर्ण है।
 - CCOSW भारतीय सेना के संचार नेटवर्क को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने, भारतीय सेना के नेटवर्क के लिये साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करेगा।

सम्मेलन के अन्य प्रमुख बिंदु:

- प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का समन्वय:
 - सभी सुरक्षा बलों में बेहतर आधुनिक संचार प्रणालियों और नेटवर्क की सुविधा प्रदान करना।
- बल संरचना और अनुकूलन:
 - बल संरचना और अनुकूलन, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन, प्रक्रियाओं तथा कार्यों, मानव संसाधन प्रबंधन और एकीकरण की सहायता से प्रमुख क्षेत्रों में जारी परिवर्तनकारी पहलों की प्रगति निर्धारित करना।
 - [अग्नपिथ योजना](#) के कुशल कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श।
 - जनवरी 2024 से मौजूदा (5-वर्षीय) 1+3+1 वर्ष की तकनीकी प्रवर्षित योजना (TES) मॉडल से (4-वर्ष) 3 + 1 TES मॉडल में संक्रमण।
 - बी.टेक स्नातकों के रूप में अधिकारी प्रवेश के लिये मौजूदा पाँच वर्षीय TES मॉडल 1999 से लागू है।
 - मौजूदा मॉडल के तहत 1 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके बाद कैंडेट ट्रेनिंग वॉर्स (CTWs) में 3 वर्ष की बी.टेक डिग्री और सेना के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में 1 वर्ष की डिग्री दी जाती है।
 - आगामी नए मॉडल में CTWs में 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण होगा, इसके बाद 1 वर्ष की बेसिक मलिट्री ट्रेनिंग (BMT) होगी।
 - नए मॉडल को मार्च 2023 में [अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद \(AICTE\)](#) की मंजूरी मिल गई है।
- पैरालंपिक आयोजन:
 - [पैरालंपिक](#) आयोजनों के लिये चयनित प्रेरित सैनिकों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना।

साइबर युद्ध से निपटने हेतु भारत की पहल:

- रक्षा साइबर एजेंसी:
 - यह साइबर मुद्दों से निपटने वाला एक त्रि-सेवा अभिकरण है और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जैसे अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करता है।
 - यह अभिकरण रक्षा बलों के लिये साइबर सदिधांत, रणनीति और नीति तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। यह साइबर क्षेत्र में संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यास एवं संचालन का भी आयोजन करता है।
- [भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल](#) (Indian Computer Emergency Response Team- CERT-In):
 - यह साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के मामले में तीव्रता से कारवाई करने और विभिन्न क्षेत्रों को साइबर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- [राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र](#) (National Critical Information Infrastructure Protection Centre- NCIIIPC):
 - यह देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, जैसे- वित्त, बैंकिंग, रक्षा आदिकी सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय एजेंसी है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर):
 - यह संक्रमित उपकरणों का पता लगाने और वायरस को हटाने तथा मालवेयर विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करने हेतु एक मंच है।

आगे की राह

- एक ऐसी व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करना जो भारतीय सशस्त्र बलों में अन्य साइबर सुरक्षा क्षमताओं के साथ **CCOSW** को एकीकृत करे, ताकि साइबर हमलों हेतु सहज समन्वय एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- भारतीय सेना के सभी कर्मियों हेतु साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक संचार प्रणालियों एवं नेटवर्क में निवेश करना जारी रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे साइबर खतरों की पहचान करने तथा उनका सामना करने के लिये आवश्यक कौशल से युक्त हों।
- उभरते सुरक्षा परिदृश्यों के आलोक में साइबर सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं की नियमिति समीक्षा एवं अद्यतन करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय सेना भविष्य में साइबर खतरों से निपटने हेतु तैयार रहे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

?????????:

प्रश्न. भारत में किसी व्यक्ति के लिये साइबर बीमा कराने पर अधिकी हानिकी भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः नमिंलखिति में से कौन-कौन से लाभ दयि जाते हैं? (2020)

1. यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक पहुँच बाधति कर देता है, तो कंप्यूटर परणाली को पुनः प्रचालति करने में लगने वाली लागत ।
2. यदि यह प्रमाणति हो जाता है ककिसी शरारती तत्त्व द्वारा जान-बूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत ।
3. यदि साइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये वशिषज्ज परामरशदाता की सेवाएँ लेने पर लगने वाली लागत ।
4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना नमिनलखिति में से कसिके/कनिके लयि वधिति: अधदिशातमक है? (2017)

1. सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर)
2. डेटा सेंटर
3. कॉरपोरेट नकियाय (बॉडी कॉरपोरेट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

?????

प्रश्न. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (2022)

स्रोतः द हृदि

सस्टेनेबल एवैशन फ्यूल

प्रलमिस के लयि:

सतत् वमिनन ईधन (SAF), यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एवैशन एडमनिसिट्रेशन क्लयिरगि हाउस, ASTM D4054 प्रमाणन, ASTM इंटरनेशनल, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अंतर्राष्ट्रीय नागर वमिनन संगठन (ICAO), वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्लीन स्काई फॉर टुमॉरो इनशिएटिवि ।

मेन्स के लयि:

शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को प्राप्त करने में सतत् वमिनन ईधन (SAF) का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद](#) (Council of Scientific and Industrial Research- CSIR) की एक प्रयोगशाला, [भारतीय पेट्रोलियम संस्थान](#) (Indian Institute of Petroleum- IIP) ने [बोइंग](#), [इंडगो](#), [स्पाइसजेट](#) और [तीन टाटा एयरलाइंस- एयर इंडिया](#), [वसितारा](#) और [एयरएशिया इंडिया](#) के साथ सतत् वमिनन ईधन के उत्पादन के लयि साझेदारी की है ।

सतत् वमिनन ईधन/सस्टेनेबल एवैशन फ्यूल:

परचिय:

- इसे [बायो-जेट फ्यूल](#) भी कहा जाता है, इसके उत्पादन [राष्ट्रीय स्तर पर वकिसति तकनीकों](#) का उपयोग करके कयिा जाता है जसिमें [खाना पकाने के तेल और उच्च तेल वाले पौधों के बीजों](#) का इस्तेमाल कयिा जाता है ।
- [ASTM इंटरनेशनल](#) द्वारा [ASTM D4054 प्रमाणीकरण](#) के लयि आवश्यक मानकों को पूरा करने हेतु [संस्थानों द्वारा उत्पादति इस ईधन के नमूनों का संयुक्त राष्ट्र फेडरल एवैशन एडमनिसिट्रेशन क्लीयरगि हाउस में सख्त परीक्षण](#) कयिा जा रहा है ।

उत्पादन का स्रोत:

- [CSIR-IIP](#) ने [गैर-खाद्य और खाद्य तेलों](#) के साथ-साथ [खाना पकाने के लयि उपयोग में लाए जाने वाले तेल](#) जैसे [वभिन्न सामग्रियों](#) का उपयोग करके ईधन तैयार कयिा है ।
- उन्होंने [पाम स्टीयरनि](#), [सैपयिम ऑयल](#), [पाम फैटी एसडि डसिटिलेट्स](#), [शैवाल तेल](#), [करंजा](#) और [जेट्रोफा](#) सहति [वभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल कयिा](#) ।

भारत में सतत् वमिनन ईधनउत्पादन के लाभ:

- भारत में SAF के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने से [GHG उत्सर्जन](#) को कम करने, [वायु गुणवत्ता में सुधार](#), [ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि](#), [नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजति करने तथा संधारणीय विकास को बढ़ावा देने](#) सहति कई लाभ मलि सकते हैं ।
- यह [वमिनन उद्योग](#) को अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने और [जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों](#) में योगदान करने में भी मदद कर सकता है ।
- [वमिनन के लयि जैव ईधन](#) को नयिमति जेट ईधन के साथ मलिाकर उपयोग कयिा जा सकता है । पारंपरिक ईधन की तुलना में इसमें [सल्फर की मात्रा कम](#) होती है जो [वायु प्रदूषण को कम कर सकता है](#) और [शुद्ध शून्य उत्सर्जन](#) को प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान दे सकता है ।
- [वमिनन हेतु जैव ईधन](#) को नयिमति जेट ईधन के साथ मलिाकर एक साथ उपयोग कयिा जा सकता है । पारंपरिक ईधन की तुलना में इसमें [सल्फर की मात्रा कम](#) होती है, जो [वायु प्रदूषण को कम कर सकता है](#) एवं [नेट जीरो \(शुद्ध शून्य\) उत्सर्जन](#) प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन कर सकता है ।

ASTM प्रमाणन:

- [ASTM इंटरनेशनल](#), जसि पहले अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स के नाम से जाना जाता था, एक वैश्विक संगठन है जो [उत्पादों, सामग्रियों एवं प्रणालियों की एक वसित्त शृंखला हेतु तकनीकी मानकों को वकिसति तथा प्रकाशति करता है](#) ।
- [ASTM मानकों](#) का उपयोग उद्योग, सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा तथा वशि्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु कयिा जाता है ।
- ASTM प्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जसिके द्वारा कसिी उत्पाद या सामग्री का परीक्षण और प्रासंगिक [ASTM मानकों के खलिाफ मूल्यांकन कयिा जाता है](#) ।
- प्रमाणन का उपयोग यह प्रदर्शति करने हेतु कयिा जा सकता है किकोई उत्पाद या सामग्री कुछ आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे [प्रदर्शन वनिरिदेश](#), [सुरक्षा मानक](#) या [पर्यावरण नयिम आदि](#) ।

वर्शिव में SAF को बढ़ावा देने हेतु पहल:

- **CORSIA प्रोग्राम:** [अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन \(International Civil Aviation Organization- ICAO\)](#) ने विमानन उत्सर्जन को उजागर करने हेतु कार्बन ऑफसेटिंग एंड रडिकेशन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) की स्थापना की है।
 - **CORSIA एयरलाइनों** को वर्ष 2020 के स्तर से ऊपर किसी भी उत्सर्जन को ऑफसेट करने की आवश्यकता है और यह प्राथमिक रूप से उत्सर्जन को कम करने हेतु SAF के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **क्लीन स्काई फॉर टुमोरो पहल:** [वर्शिव आर्थिक मंच](#) ने क्लीन स्काई फॉर टुमोरो पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य SAF के उत्पादन और उपयोग में तेज़ी लाना है।
 - यह पहल SAF उत्पादन को विकसित करने और बढ़ाने में सहयोग करने हेतु विमानन, ईंधन एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाती है।
- **SAF सम्मिश्रण लक्ष्य:**
 - [यूरोपीय संघ](#) ने विमानन से GHG उत्सर्जन को कम करने हेतु **स्थायी विमानन ईंधन** हेतु सम्मिश्रण लक्ष्य स्थापित किया है जिसका उद्देश्य समय के साथ विमानन ईंधन में SAF के उपयोग को बढ़ाना है।
 - वर्ष 2025 से गैसोलीन और मट्टी तेल से बने पारंपरिक जेट ईंधन के साथ SAF का सम्मिश्रण 2 प्रतिशत से शुरू होगा।
 - वर्ष 2050 में 63 प्रतिशत SAF सम्मिश्रण तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ सम्मिश्रण लक्ष्य प्रत्येक पाँच साल में बढ़ेगा।
- **सस्टेनेबल स्काइज़ एक्ट और SAF उत्पादन प्रोत्साहन:**
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में सतत विमानन ईंधन (SAF) के उपयोग और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये अमेरिकी कॉंग्रेस नेमई 2021 में सस्टेनेबल स्काइज़ एक्ट पेश किया।
 - सस्टेनेबल स्काइज़ एक्ट अमेरिका में SAF-उत्पादक सुविधाओं की संख्या बढ़ाने के लिये पाँच वर्षों में 1 बिलियन डॉलर का अनुदान प्रदान करता है।
- **नोट:** ईंधन के कुछ अन्य स्थायी स्रोत जिन पर भारत काम कर रहा है, में शामिल हैं:
 - [बायोडीज़ल](#)
 - [पारंपरिक ईंधन में इथेनॉल सम्मिश्रण](#)
 - [हाइड्रोजन ईंधन सेल](#)

SAF से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **उच्च लागत:** SAF के उत्पादन की लागत वर्तमान में पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में अधिक है, जिससे एयरलाइनों के लिये SAF उत्पादन और उपयोग में निवेश करना आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य हो जाता है।
- **संसाधन उपलब्धता:** SAF के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिये सीमाति बुनियादी ढाँचा है, जिससे SAF के उत्पादन एवं आपूर्ति को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।
- **फीडस्टॉक उपलब्धता:** SAF उत्पादन के लिये फीडस्टॉक की उपलब्धता सीमाति है और खाद्य तथा कृषि क्षेत्रों जैसे अन्य उद्योगों के बीच संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा है।
- **प्रमाणन:** SAF के लिये प्रमाणन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है तथा SAF उत्पादन के लिये वर्शिव स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों की कमी है।
- **जन जागरूकता:** सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और SAF के लाभों की समझ बढ़ाने तथा नीति निर्माताओं एवं निवेशकों से अधिक समर्थन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **निवेश में वृद्धि:** सरकारों, एयरलाइंस और निवेशकों को लागत कम करने तथा उपलब्धता बढ़ाने के लिये SAF उत्पादन एवं बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसमें R&D के वित्तपोषण के साथ-साथ नई सुविधाओं का निर्माण करना और SAF के उत्पादन हेतु मौजूदा सुविधाओं को जारी रखना शामिल है।
- **समर्थन नीति और नियामक ढाँचे:** सरकारें SAF के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली नीति और नियामक ढाँचे को लागू कर सकती हैं, जैसे- कर प्रोत्साहन, सब्सिडी और SAF के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने के लिये एयरलाइनों हेतु आदेश।
- **सहयोग को प्रोत्साहित करना:** एयरलाइंस, ईंधन उत्पादकों और अनुसंधान संस्थानों सहित हितधारकों के बीच सहयोग से अधिक एकीकृत और कुशल SAF आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद मिल सकती है।
- **जन जागरूकता को बढ़ावा देना:** यह SAF के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और टिकाऊ विमानन की आवश्यकता की मांग बढ़ाने तथा नीति निर्माताओं एवं निवेशकों को अधिक समर्थन के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
- **नए फीडस्टॉक स्रोत विकसित करना:** SAF उत्पादन के लिये नए फीडस्टॉक स्रोत विकसित करने हेतु अनुसंधान में निवेश, जैसे- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट, फीडस्टॉक उपलब्धता बढ़ाने तथा अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा को कम करने में मदद कर सकता है।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

टी फोर्टफिकेशन

प्रलिमिस के लिये:

फोर्टफिकेशन, फोलेट और विटामिन B12, एनीमिया, भारत में फोर्टफिकेशन प्रोग्राम

मेन्स के लिये:

भोजन के फोर्टफिकेशन से जुड़े मुद्दे और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

फोलेट और विटामिन B12 के साथ फोर्टफाइंग टी/चाय के प्रभाव का आकलन करने हेतु 43 महिलाओं पर महाराष्ट्र में हाल ही में किये गए एक अध्ययन में फोलेट एवं विटामिन B12 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसने हिमोग्लोबिन के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी प्रकाश डाला।

- हालाँकि अध्ययन अपने नमूने के आकार के कारण ज़्यादातर गलत साबित हुआ है।

टी फोर्टफिकेशन प्रभावकारी परिवर्तन/गेम-चेंजर:

- **एनीमिया और NTD से मुकाबला:** नए अध्ययन के अनुसार, फोलेट और विटामिन B12 के साथ फोर्टफाइंग चाय भारतीय महिलाओं में एनीमिया और NTD का मुकाबला करने में मदद कर सकती है क्योंकि चाय भारत में पिया जाने वाला सबसे आम पेय पदार्थ है।
 - अधिकांश भारतीय महिलाओं द्वारा खराब आहार फोलेट और विटामिन B12 का सेवन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विटामिन की स्थिति लगातार कम होती है, जो एनीमिया को बढ़ाता है, यही कारण है कि भारत में फोलेट-उत्तरदायी न्यूरोल-ट्यूब दोष (Neural-Tube Defects- NTD) की उच्च घटनाएँ होती हैं।
 - शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन हेतु विटामिन B12 और फोलेट दोनों महत्वपूर्ण हैं।
 - शरीर में फोलेट के उचित अवशोषण और उपयोग हेतु विटामिन B12 आवश्यक है क्योंकि फोलेट की कमी से गंभीर जन्म दोष (NTDs) हो सकते हैं।

नोट: न्यूरोल ट्यूब की समस्या तब होती है जब भ्रूण के विकास के दौरान न्यूरोल ट्यूब पूरी तरह से बंद नहीं होती है। न्यूरोल ट्यूब अंततः मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और आसपास के ऊतकों का निर्माण करती है।

टी फोर्टफिकेशन संबंधी मुद्दे:

- **सीमिति खेती:** चाय बड़े पैमाने पर केवल 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उगाई एवं संसाधित की जाती है।
- **अवसरचना की कमी:** कई चाय उगाने वाले क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चाय के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचे कमी है।
 - इसमें चाय के सम्मिश्रण और पैकेजिंग के साथ-साथ परिवहन और भंडारण के बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ शामिल हैं।
- **आहार संबंधी बाधाएँ:** लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है, जहाँ अनाज अधिक बार उगाया एवं साफ किया जाता है तथा स्थानीय स्तर पर खरीदा जाता है। सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जातीय मतभेदों व विश्वासों के अनुसार आहार प्रकृति काफी भिन्न होती है।

फूड फोर्टफिकेशन:

परिचय:

- चावल, दूध और नमक जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों में आयरन, आयोडीन, जंक, विटामिन A और D जैसे प्रमुख विटामिन तथा खनिजों को शामिल करना **फोर्टफिकेशन** है, ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके। प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्व भोजन में मूल रूप से मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

भारत में फूड फोर्टफिकेशन की स्थिति:

- **चावल:** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) "चावल के फोर्टफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके वितरण पर केंद्र प्रयोजित पायलट योजना" चला रहा है।

- योजना को तीन साल के पायलट अवधि के लिये वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया था।
- यह योजना वर्ष 2023 तक चलेगी और **लाभार्थियों को 1 रुपए किलो की दर** से चावल की आपूर्तिकी जाएगी।
- **गेहूँ:** गेहूँ के फोर्टिफिकेशन पर नरिणय की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी और बच्चों, कशिरों, गर्भवती माताओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार के लिये भारत के प्रमुख **पोषण अभियान** के तहत 12 राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है।
- **खाद्य तेल:** वर्ष 2018 में FSSAI द्वारा देश भर में खाद्य तेल का फोर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया था।
- **दूध:** वर्ष 2017 में **भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** ने कंपनियों को विटामिन D मलाने के लिये प्रोत्साहित करके दूध के फोर्टिफिकेशन की शुरुआत की।

■ महत्त्व:

- **व्यापक जनसंख्या स्वास्थ्य सुधार:** चूँकि व्यापक रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में पोषक तत्त्वों का योग किया जाता है, यह **आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य में एक साथ सुधार लाने का एक उत्कृष्ट तरीका** है।
- **सुरक्षित तरीका:** फोर्टिफिकेशन लोगों के बीच पोषण में सुधार का एक सुरक्षित तरीका है।
 - **यदि मिलाई गई मात्रा को निर्धारित मानकों के अनुसार** अच्छी तरह से वनियमित किया जाता है तो पोषक तत्त्वों की अधिक मात्रा की संभावना नहीं होती है।
- **खाने की आदतों पर कोई प्रभाव नहीं:** इसे खाने की आदतों और लोगों के पैटर्न में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है और यह लोगों को पोषक तत्त्व प्रदान करने का एक सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका है।
 - यह भोजन की विशेषताओं- स्वाद, स्पर्श, रूप में भी परिवर्तन नहीं करता है।
- **लागत प्रभावी:** यह वधिलगत प्रभावी है, विशेष रूप से यदि भोज्य पदार्थों की और वितरण प्लेटफॉर्म का समुचित लाभ उठाया जाता है।
 - कोपेनहेगन सहमति (Copenhagen Consensus) का अनुमान है कि **फूड फोर्टिफिकेशन पर व्यय किया गया प्रत्येक 1 रुपया अर्थव्यवस्था के लिये 9 रुपए का लाभ उत्पन्न करता है।**

■ चुनौतियाँ:

- भारत में केवल कुछ खाद्य पदार्थों (गेहूँ, चावल, नमक) के लिये खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, कई अन्य खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड नहीं किया जाता है, **जिससे पोषक तत्त्वों का सेवन अपर्याप्त हो जाता है।**
- **सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को मलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे- फाइटोकेमिकल्स और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।**
- **गर्भवती महिलाओं द्वारा अधिक आयरन का सेवन करने से भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है** और जन्म के समय बच्चों में पुरानी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ सकता है।
- फोर्टिफिकेशन, **बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये एक गारंटीकृत बाजार प्रदान कर सकता है**, जो पूरे भारत में छोटे व्यवसायों की **आजीविका को संभावित रूप से नुकसान पहुँचा सकता है।**
- जोड़े गए विटामिन और खनिजों की अस्थिरता के कारण दूध एवं तेल जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

टी फोर्टिफिकेशन से संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु आवश्यक कदम:

- **सरकार का हस्तक्षेप:** चाय के पोषण में वृद्धि करने के लिये नीतियों और वनियमों को लागू करके सरकार टी फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
 - उदाहरण के लिये सरकार चाय निर्माताओं हेतु आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की मात्रा में वृद्धि करना अनिवार्य कर सकती है।
- **उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा देना:** चाय निर्माता अनुसंधान एवं शोध में निवेश करके और बाजार में फोर्टिफाइड चाय उत्पादों को पेश करके चाय के फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं।
 - वे फोर्टिफाइड चाय के लाभों को बढ़ावा देने के लिये सरकार और गैर-लाभकारी संगठनों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना:** उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चाय के लाभों के बारे में शिक्षित करने से इसकी खपत को बढ़ावा देने में काफी मदद मिल सकती है।
 - यह विभिन्न माध्यमों जैसे वजिापन अभियान, सोशल मीडिया और स्कूलों एवं कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **रसद में सुधार:** बड़े पैमाने पर चाय के फोर्टिफिकेशन को लागू करने के लिये एक मजबूत रसद प्रणाली का होना आवश्यक है।
 - इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पोषण तत्त्वों के किसी भी नुकसान के बिना फोर्टिफाइड चाय लक्षित आबादी तक समय पर और कुशल तरीके से पहुँचे।

स्रोत: द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[ठोस अपशषिट प्रबंधन](#), [लैंडफिल](#), [यूएनईपी](#), [ठोस अपशषिट प्रबंधन नियम 2016](#), [पशु जनन नियंत्रण कार्यक्रम](#) ।

मेन्स के लिये:

आवारा कुत्तों और ठोस अपशषिट प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, आगे की राह ।

चर्चा में क्यों?

श्रीनगर में आवारा कुत्तों के हमलों की एक हालिया घटना ने स्ट्रीट डॉग्स के हमलों और खराब ठोस अपशषिट प्रबंधन के बीच संबंध को उजागर किया है ।

खराब अपशषिट प्रबंधन और स्ट्रीट डॉग्स द्वारा बढ़ते हमलों में संबंध:

- भारतीय घरों ने औसतन 2019 में प्रतिव्यक्ति 50 किलोग्राम खाद्य अपशषिट उत्पन्न किया, जो भूखे-पीड़ित, खुले में घूमने वाले कुत्तों के लिये भोजन के स्रोत के रूप में काम करता है जिससे वे शहरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं ।
 - यह भोजन अक्सर शहरी क्षेत्रों में भूख से पीड़ित आवारा कुत्तों के लिये भोजन का स्रोत बन जाता है, जो भोजन की तलाश [लैंडफिल या अपशषिट डंप](#) जैसे कचरा डंपिंग साइटों के आसपास घूम रहे होते हैं ।
- जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि नगर नगिम के कचरे और इसके कुप्रबंधन ने सीधे तौर पर कुत्तों के काटने, सुस्त पशु जनन नियंत्रण कार्यक्रमों और अपर्याप्त बचाव केंद्रों के साथ-साथ खराब अपशषिट प्रबंधन में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सड़क पर रहने वाले जानवरों का प्रसार हुआ और जिसके कारण हमले हुए ।

भारत के ठोस अपशषिट प्रबंधन के साथ क्या समस्या है?

■ परदृश्य:

- ठोस अपशषिट में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशषिट जैसे सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इस्टीट्यूशनल वेस्ट, खानपान और बाज़ार का अपशषिट और अन्य गैर-आवासीय वेस्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई गाद, बागवानी वेस्ट, कृषि और डेयरी वेस्ट, औद्योगिक अपशषिट को छोड़कर उपचारित बायोमेडिकल अपशषिट, बायो-मेडिकल वेस्ट तथा ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, रेडियो-एक्टिव वेस्ट आदि शामिल हैं ।
- भारत में वशिव की आबादी का लगभग 18% और वैश्विक नगरपालिका अपशषिट उत्पादन में 12% का योगदान है ।
 - भारत प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन अपशषिट उत्पादन करता है । इनमें से लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन को उपचारित किया जाता है तथा 31 मिलियन टन लैंडफिल साइट्स में फेंक दिया जाता है ।
- खपत के बदलते पैटर्न और तेज़ी से आर्थिक विकास के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 में शहरी नगरपालिका ठोस अपशषिट उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगा ।

■ मुद्दा:

○ नयियों का खराब क्रियान्वयन:

- वर्ष 2020 के एक शोध पत्र में कहा गया है कि अधिकांश मेट्रो शहरों में अपशषिट को संग्रह करने वाले डबिबे या तो पुराने हैं या क्षतिग्रस्त हैं या ठोस अपशषिट को रखने के लिये अपर्याप्त हैं ।
- अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी स्थानीय निकाय [ठोस अपशषिट प्रबंधन नियम 2016](#) के तहत नयियों को लागू करने और बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे- घर-घर जाकर अलग-अलग प्रकार के अपशषिट का संग्रह करना ।
- नयियों के तहत कचरा संग्रह स्थल निर्धारित हैं, लेकिन नयियों के कार्यान्वयन और जागरूकता की कमी है ।
- इसके कारण इधर-उधर बिखरा अपशषिट देखा जाता है ।

○ मलिन बस्तियों के साथ डंपिंग साइट्स की नकटता:

- अधिकांश लैंडफिल और डंपिंग साइट शहरों की परिधि में, झुग्गी बस्तियों और बस्ती कॉलोनियों के बगल में स्थित हैं ।
- मुंबई में सबसे सस्ते आवास देवनार के पास पाए जा सकते हैं जो 256 झुग्गियों और 13 पुनर्वास कॉलोनियों के नकट स्थित हैं ।
- शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में कुत्ते के काटने के मामले बेहिसाब आते रहते हैं । रपॉर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में पुणे के शविनेरी नगर झुग्गी में रहने वाले 300 लोगों ने इलाके में आवारा कुत्तों के काटने की शिकायत की थी ।

○ डेटा संग्रह तंत्र का अभाव:

- भारत में ठोस अथवा तरल अपशषिट के संबंध में समयबद्ध डेटा अथवा पैनल डेटा की कमी है, जिससे नज्जी संस्थाओं के लिये अपशषिट प्रबंधन नीतियों की लागत और लाभों के बीच संबंध को समझना मुश्किल हो जाता है।

अपशषिट प्रबंधन से संबंधित पहल:

■ ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम 2016:

- ये कानून, जो नगरपालिका ठोस अपशषिट (प्रबंधन और हैंडलिंग) कानून, 2000 को प्रतस्थापित करते हैं, स्रोत पर अपशषिट पृथक्करण, सैनटिरी और पैकेजिंग अपशषिट के नपिटान हेतु नरिमाता की ज़मिमेदारी एवं बल्क जनरेटर से संग्रह, नपिटान तथा प्रसंस्करण के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क पर ज़ोर देते हैं।

■ वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल:

- इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।

■ अपशषिट से ऊर्जा:

- अपशषिट-से-ऊर्जा या ऊर्जा-से-अपशषिट संयंत्र औद्योगिक प्रसंस्करण के लिये नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशषिट को वदियुत और/या ऊष्मा में परिवर्तित करता है।

■ प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन (PWM) नयिम, 2016:

- यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक अपशषिट को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर अपशषिट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
- फरवरी 2022 में प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन (संशोधन) नयिम, 2022 को अधिसूचित किया गया था।

■ प्रोजेक्ट रप्लान (REPLAN):

- इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास के रेशों के साथ प्रसंस्कृत एवं उपचारित प्लास्टिक अपशषिट को मिलाकर कैरी बैग बनाना है।

■ प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन (संशोधन) नयिम, 2022:

- नयिम वभिन्नि हतिधारकों जैसे- नरिमाताओं, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की ज़मिमेदारियों को नरिदषिट करते हैं। इन सभी हतिधारकों को यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभानी है कि प्लास्टिक अपशषिट का उचित प्रबंधन किया जाए एवं इससे पर्यावरण प्रदूषित न हो।

आगे की राह

- सार्वजनिक स्थानों पर अपशषिट प्रबंधन में सुधार और बेकरियों के आसपास भोजन को वनियिमति करने से पर्यावरण की वहन क्षमता कम हो सकती है।
- ऐसी घटनाओं को कम करने हेतु अपशषिट नपिटान सुविधाओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल कुत्तों की नसबंदी और टीकों पर नरिभर रहना पर्याप्त नहीं होगा।
- सामुदायिक स्तर पर विकेंद्रीकृत अपशषिट प्रबंधन प्रणालियाँ शुरू की जा सकती हैं ताकि एक केंद्रीकृत स्थान पर बड़ी मात्रा में नगर नगिम के कचरे को संभालने का बोझ कम किया जा सके। अनौपचारिक श्रमिकों के लिये नौकरी के अवसर प्रदान किये जा सकें और परिवहन एवं भंडारण लागत को कम किया जा सके।
- अपशषिट प्रबंधन में सकरयि भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये वशिववदियालय और स्कूल स्तर पर अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी-संचालित रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत में ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- अपशषिट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशषिट अलग-अलग करने होंगे।
- ये नयिम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय नकियों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
- इन नयिमों में अपशषिट भराव स्थलों तथा अपशषिट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और वसितृत मानदंड उपबंधित हैं।
- अपशषिट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशषिट, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नरितर उत्पन्न कयि जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की वशिल मात्रा का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशष्टिों को सुरक्षति रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/01-05-2023/print>

